बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 102 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 30 जनवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

तस्करी पर शिकंजा: दिल्ली में करीब 10 करोड़ रुपये कीमत का मादक पदार्थ जब्त, बैंकॉक से आया यात्री गिरफ्तार

नई दिल्ली । इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से आए एक भारतीय यात्री के पास से 9.84 किलोग्राम मारिजुआना बरामद कर उसे मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यात्री 26 जनवरी को टर्मिनल तीन पर पहुंचा था और स्मार्ट प्रोफाइलिंग के आधार पर उसे रोका गया। इसके बाद उसे ग्रीन चैनल पर उसके सामान की एक्स-रे जांच के लिए ले जाया गया, फिर विस्तृत तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान एक हरे रंग के हैंडबैग से एक तरफ काले और एक तरफ पारदर्शी कुल नौ पॉलीबैग बरामद किए गए, जिनमें कई परतों में वैक्यूम-सील पैकेट रखे हुए थे।

दिल्ली हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, Freedom of Speech के नाम पर किसी की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ नहीं

नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यद्यपि एक मौलिक अधिकार है, असीमित नहीं है और इसका उपयोग व्यक्तियों या संगठनों के विरुद्ध मानहानिकारक या अपमानजनक अभियानों को उचित ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि संविधान स्वयं अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंध लगाता है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मानहानिकारक, दुर्भावनापूर्ण या दूसरों की प्रतिष्ठा और गरिमा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से दिए गए भाषण को कवर नहीं करता है। ये टिप्पणियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला देकर कुछ वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट के प्रसार का बचाव करने के प्रयास के बाद की गईं उच्च न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी व्यक्ति या संस्था की प्रतिष्ठा या साख को नुकसान पहुंचाने का लाइसेंस नहीं माना जा सकता है। अदालत ने कहा कि जानबूझकर गरिमा या प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला भाषण संवैधानिक संरक्षण के दायरे से बाहर है। न्यायमूर्ति योति सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिष्ठा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। किसी भी प्रकार का भाषण

जो इस अधिकार का उल्लंघन करता है, उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में संरक्षण नहीं दिया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखना संवैधानिक ढांचे के लिए आवश्यक है। ये टिप्पणियां तब आईं जब न्यायालय फिजिक्सवाला लिमिटेड द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक पूर्व कर्मचारी ने यूट्यूब वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कंपनी, उसके संस्थापक और कर्मचारियों को घोटाला बताकर एक निरंतर ऑनलाइन अभियान चलाया था। कंपनी ने दावा किया कि सामग्री अपमानजनक, भ्रामक थी और इसका उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी व्यवसाय को बढ़ावा देते हुए जनता के विश्वास और सद्भावना को नुकसान पहुंचाना था। वीडियो, प्रतिलेख और रिकॉर्ड में मौजूद अन्य सामग्री की समीक्षा करने के बाद, न्यायालय ने पाया कि प्रथम दृष्टया अंतरिम राहत का मामला बनता है। न्यायालय ने माना कि सामग्री स्पष्ट रूप से मानहानिकारक और अपमानजनक प्रतीत होती है, और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा वर्षों से अर्जित प्रतिष्ठा और सद्भावना को धूमिल करना था। न्यायालय ने कहा कि प्रतिष्ठा को नुकसान अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई पैसों से नहीं की जा सकती।

न्यायालय ने यह भी कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की गति, पहुंच और स्थायित्व के कारण ऑनलाइन मानहानि का प्रभाव कहीं अधिक व्यापक और गंभीर होता है। न्यायालय ने कहा कि ऐसी सामग्री तत्काल और अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचा सकती है, इसलिए त्वरित न्यायिक कार्रवाई आवश्यक है।

Northeast पर बीजेपी का Mega Focus, अमित शाह के दौरे से सधेंगे विकास और सियासत के समीकरण

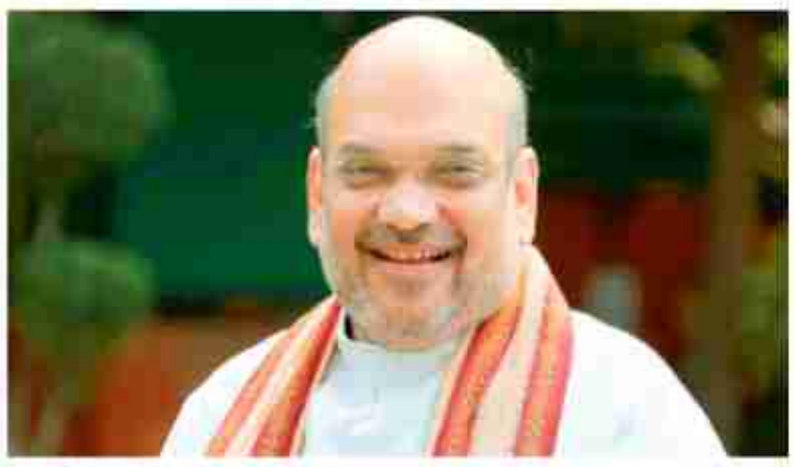

नई दिल्ली ।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 जनवरी (शुक्रवार) को राज्य के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान असम विधानसभा भवन और वन्यजीव अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस दौरे में शाह राय भर में कई आधिकारिक, सांस्कृतिक और संगठनात्मक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। दौरे की शुरुआत डिब्रूगढ़ से होगी, जहां गृह मंत्री असम विधानसभा भवन और वन्यजीव अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखेंगे, जो राय के विधायी ढांचे और वन्यजीव संरक्षण ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी अवसर पर, शाह ऊपरी असम में खेल अवसंरचना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई खानिकर स्टेडियम परियोजना के प्रथम चरण का भी उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम सुबह लगभग 10:30 बजे डिब्रूगढ़ के खानिकर में आयोजित किया जाएगा। राज्य सरकार के अधिकारियों ने बताया कि नए विधानसभा परिसर को आधुनिक सुविधाओं से लैस एक आधुनिक विधायी सुविधा के रूप में परिकल्पित किया गया है, जबकि वन्यजीव अनुसंधान संस्थान असम की समृद्ध जैव विविधता के वैज्ञानिक अनुसंधान, संरक्षण और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बाद में केंद्रीय गृह मंत्री दोपहर 12:15 बजे करेन्ग चापोरी में आयोजित होने वाले 10वें मिशिंग सांस्कृतिक महोत्सव में भाग लेने के लिए धेमाजी जाएंगे। मिशिंग समुदाय द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित यह महोत्सव पारंपरिक नृत्य, संगीत, कला, वेशभूषा और स्थानीय भोजन के माध्यम से जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है। शाह गुवाहाटी पहुंचेंगे और असम राय कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में संगठनात्मक मामलों, आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों और राज्य में जमीनी स्तर पर संपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। पार्टी की असम इकाई के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री को चल रही पहलों, संगठनात्मक तैयारियों और भविष्य की रणनीतियों के बारे में जानकारी देंगे। उम्मीद है कि यह बैठक आगामी राजनीतिक गतिविधियों से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेगी। असम में विकास पहलों, सांस्कृतिक गतिविधियों और संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में शाह की यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हमारे बीच सब ठीक, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात कर बोले शशि थरूर

नई दिल्ली।

कांग्रेस से तनातनी की अटकलों के बीच तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की है। यह मुलाकात संसद भवन में लगभग 90 मिनट तक हुई। मीटिंग के बाद थरूर ने पत्रकारों से कहा, हमारी बहुत अच्छी, रचनात्मक और सकारात्मक बातचीत हुई। सब कुछ ठीक है और हम सब एक ही पेज पर आगे बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि शशि थरूर ने ही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे से मिलने का समय मांगा था ताकि वे अपने विचार और चिंताएं बता सकें। यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले पार्टी इन शिकायतों को दूर करने की कोशिश करेगी । पिछले साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद थरूर के कांग्रेस के साथ संबंध तेजी से खराब होते दिखे। तिरुवनंतपुरम से चार बार के लोकसभा सांसद ने प्रधानमंत्री द्वारा संकट से निपटने के तरीके की जमकर तारीफ की थी, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। इनमें से कई नेताओं ने थरूर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का न्योता पाने की कोशिश करने का ताना भी मारा था। इसके अगले कुछ महीनों में रिश्ते और खराब होते दिखे, जिनमें नवंबर 2025 की दो घटनाएं शामिल हैं। पहली घटना तब हुई जब थरूर एक प्राइवेट इवेंट में गए जहां प्रधानमंत्री बोल रहे थे और फिर उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, यह भाषण एक आर्थिक आउटलुक और सांस्कृतिक बदलाव का आह्वान था, जो देश को तरक्की के लिए बेचैन होने के लिए प्रेरित करता है। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत और संदीप दीक्षित ने इस पर पलटवार करते हुए भाषण को बकवास बताया और थरूर की टिप्पणियों पर सवाल उठाए। नवंबर में दूसरी घटना इंडियन पॉलिटिक्स आर ए फैमिली बिजनेस नाम के एक आर्टिकल की थी। इसमें कांग्रेस जैसी परिवार-आधारित पार्टियों की आलोचना की गई थी, जो पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं आई।

मीटिंग के बाद थरूर ने पत्रकारों से कहा, हमारी बहुत अच्छी, रचनात्मक और सकारात्मक बातचीत हुई। सब कुछ ठीक है और हम सब एक ही पेज पर आगे बढ़ रहे हैं।

दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला : Illegal Immigrant होना अनिश्चितकाल जेल का आधार नहीं, बिलाल हुसैन को राहत

नई दिल्ली ।

साकेत जिला न्यायालय ने अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी बिलाल हुसैन की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि उसने न तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है और न ही जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी एक अवैध अप्रवासी है, जो उसे अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। वह फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन में वर्ष 2024 में दर्ज एक एफआईआर में आरोपी है। उसे 28 दिसंबर, 2024 को गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) गौरव गुप्ता ने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा बिलाल हुसैन को दी गई जमानत रद्द करने की दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि आरोपी ने किसी भी तरह से उसे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है या उसने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है। एएसजे गुप्ता ने 28 जनवरी के आदेश में कहा, केवल इस तथ्य के आधार पर कि आरोपी एक अवैध अप्रवासी है, उसे अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। इस स्तर पर, आरोपी को दी गई जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई नए तथ्य सामने आते हैं या जांच एजेंसी द्वारा कोई नया सबूत जुटाया जाता है जिससे आरोपी को हिरासत में रखना आवश्यक हो, तो अभियोजन पक्ष इस संबंध में एक नया आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें 24 नवंबर, 2025 को जमानत दी थी। राय ने जमानत रद्द करने के लिए आवेदन दिया था। अधिवक्ता हर्षित पांडे आरोपी बिलाल हुसैन की ओर से पेश हुए। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि आरोपी बांग्लादेशी नागरिक है जिसने अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था। इसके अलावा, उसने आधार कार्ड सहित भारतीय पहचान पत्र प्राप्त किए थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसकी सूचना पर विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर कई आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद किए गए। आरोप है कि आरोपी बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में अवैध रूप से प्रवेश कराने और उनके लिए भारतीय पहचान पत्र प्राप्त करने में सहायक था। पूछे जाने पर, जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी के पास से बरामद आधार कार्डों का सत्यापन अभी बाकी है, क्योंकि यूआईडीएआई से जवाब का इंतजार है। आरोपी बिलाल हुसैन को भारत-बांग्लादेश सीमा को अवैध रूप से पार करते हुए पकड़ा गया था, और उसकी सूचना पर बरामद की गई वस्तुओं में बांग्लादेशी नागरिकों के नाम पर आधार कार्ड और पांच पैन कार्ड तथा बांग्लादेशी पहचान पत्र शामिल हैं। पुलिस ने उसकी जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि उसके भाई अनीश शेख को अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है। यह भी कहा गया कि यदि आरोपी को जमानत दी जाती है, तो वह अदालत की कार्यवाही से भाग सकता है और अन्य वांछित व्यक्तियों को चेतावनी दे सकता है।

चुनावी वर्ष से पहले सत्या शर्मा का आक्रामक बजट, वित्तीय सुधारों पर जोर; आम आदमी पार्टी पर वार

नई दिल्ली । एमसीडी की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने वर्ष 2026-27 का बजट पूरी तरह चुनावी माहौल की तरह प्रस्तुत किया। बजट भाषण के दौरान उन्होंने न केवल विकास योजनाओं और वित्तीय सुधारों पर जोर दिया, बल्कि सवा दो साल तक एमसीडी में शासन करने वाली आम आदमी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप अपने कार्यकाल में एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं कर पाई और जनता को केवल भ्रमित करने का काम किया। सत्या शर्मा ने कहा कि एमसीडी चुनाव के समय आम आदमी पार्टी ने 10 गारंटियां दी थीं, लेकिन निगम में शासन के दौरान उनमें से किसी एक पर भी अमल नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि आप के कार्यकाल में न तो निगम की वित्तीय स्थिति सुधरी न ही सफाई, स्वास्थ्य या बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर कोई ठोस काम हुआ। इसके उलट भाजपा सरकार ने अपने 100 दिन के शासन में ही 12 में से तीन वादे पूरे कर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सत्ता संभालते ही एमसीडी को आर्थिक संकट से उबारने की दिशा में काम शुरू किया। वर्षों बाद निगम ने मुनाफे का बजट प्रस्तुत किया है, जो इस बात का प्रमाण है कि भाजपा केवल वादे नहीं करती, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारती है। सत्या शर्मा ने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि एमसीडी का भविष्य विजन और मिशन है। एमसीडी के अगले चुनाव वर्ष 2027 में प्रस्तावित हैं। इसके बावजूद बजट भाषण में जिस तरह की घोषणाएं, योजनाएं और राजनीतिक तेवर देखने को मिले, उसने इसे पूरी तरह चुनावी बजट का रूप दे दिया। सफाई व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन, वायु प्रदूषण नियंत्रण, पार्किंग, पार्कों का विकास, कर्मचारियों के हित, पार्षदों की सुविधाएं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान समेत हर वर्ग को साधने की कोशिश बजट में साफ नजर आई।

सिखों की देशभक्ति पर गर्व

एक समय था जब भारतीय फौज में सिखों की गिनती सबसे अधिक हुआ करती थी। सिख युवक सिख रेजीमेंट के अलावा सिख इन्फैंट्री, पंजाब रेजीमेंट, आर्टिलरी, गोरखा, आरमर्ड सहित अन्य रेजीमेंट में भी बड़ी गिनती में भर्ती हुआ करते थे। सिख रेजीमेंट सबसे अधिक मैडल जीतने वाली रेजीमेंट थी और एक समय में तो कामनवेल्थ में सबसे ऊपर इसका नाम आता था। पंजाब के तकरीबन हर घर से एक न एक बच्चा फौज में भेजा जाता था और कई घर तो ऐसे भी हैं जिनमें कई पीढ़ियां फौज में गईं, पर आज सिख युवकों की फौज के प्रति रुचि कम होती देख देश की सेना के द्वारा सिखों को सेना में भर्ती होकर सिख रेजीमेंट से जुड़ने की अपील की गई है जो दर्शाता है कि आज भी समूचे देश को सिखों की देशभक्ति पर गर्व है और यह भलिभांति जानते हैं कि सिख सैनिक मुश्किल आने पर कभी पीछे नहीं हटता या तो सामने वाले को मिटा देता है या फिर खुद देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। इतिहास गवाह है कि 19वीं सदी में खालसा आर्मी द्वारा अफगानिस्तान विजय करने के बहादुरी वाले किस्सों से प्रभावित होकर ब्रिटिश हकूमत ने सिखों को भारतीय फौज में शामिल करते हुए उन्हें सिख पायनियर्स का खिताब दिया गया। 1846 में सिख रेजीमेंट की स्थापना हुई। 1932 में जब स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष जोरों पर था, स्वतंत्रता संग्राम में भी सिखों द्वारा आगे आकर अंग्रेजी हकूमत के खिलाफ मोर्चे लगाए जा रहे थे, ऐसे में मार्शल कौम से गौरों को भय सताने लगा और उन्होंने सिख बटालियनों को भंग कर दिया। 1941 में दूसरे विश्व युद्ध के समय उन्हें अधिक फौज की आवश्यकता हुई तो फिर से बड़ी गिनती में सिखों को फौज में शामिल किया गया और सिख रेजीमेंट के अतिरिक्त सिख लाईट इन्फैंटरी रेजीमेंट की भी स्थापना की गई जो कि आज भी कायम है और 20 रैगुलर बटालियन, 3 टैरिटोरियल आर्मी इसमें काम कर रही है। आजादी से पूर्व 245 और आजादी के उपरांत 82 मैडल सिख रेजीमेंट के बहादुर जवानों ने जीते जिनमें 21 इंडियन आर्डर आफ मैरिट, 14 विक्टोरिया, 2 परमवीर चक्र, 4 अशोक, 8 महावीर, 24 कीर्ति, 64 वीर, 55 शौर्य चक्र के अलावा 375 सेना मैडल प्राप्त किये हैं। पहला अग्निवीर पदक हासिल करने वाला सैनिक भी 7 सिख लाईट इन्फैंटरी से आया। सिख सैनिकों की फौज में कम होती गिनती के पीछे कुछ लोग सिख युवकों का रूझान विदेशों की ओर बढ़ने का तर्क देते हैं मगर सरदार हिम्मत सिंह जिनका पारिवारिक सम्बन्ध फौज से रहा है और इनके परिवार के कई सदस्य आज भी भारतीय फौज का हिस्सा हैं। हिम्मत सिंह का कहना है कि सिखों का विदेशों में पलायन का सिलसिला तो बीसवीं सदी के शुरू से ही हो गया था, यह कोई नया नहीं है। बावजूद इसके इतने सालों से सेना में भी बड़ी गिनती में सिख भर्ती हुए। असल में जबसे राज्य की जनसंख्या के हिसाब से फौज में भर्ती होने लगी तब से पंजाब से गिनती कम होने लगी। दूसरा अग्निवीर स्कीम भी इसका एक कारण है जिसके लिए सरकार को थोड़ा बदलाव करने की आवश्यकता है। इस स्कीम के आने से सिपाही और अग्निवीर में फर्क दिखने लगा जबकि दोनों ही जवान सेना में रहकर देश के लिए मर-मिटने को तैयार रहते हैं। फिर अग्निवीर को 4 साल बाद रिटायरमेंट होने के बाद कोई पैंशन या अन्य लाभ भी नहीं है। इसलिए सिर्फ अपील से कुछ नहीं होगा, इसकी शर्तों पर विचार करने की आवश्यकता है। विदेशों से संचालित पंजाबी अंडरवर्ल्ड पंजाब जिसे गुरुओं, पीरों की धरती माना जाता है और पंजाब के लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विदेशों में जाकर पंजाब ही नहीं बल्कि समूचे देश को कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। यह लोग विदेशों में बैठकर पंजाबी अंडरवर्ल्ड चला रहे हैं जिसके चलते आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि पंजाब में गैंगस्टर कल्चर दिन-प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है जो कि बेहद चिन्ता का विषय है। इसके पीछे क्या कारण रहे, कौन इसके लिए जिम्मेवार है यह मायने नहीं रखता अब सोचना यह होगा कि इसे किस प्रकार रोका जाए। बुद्धिजीवी वर्ग का मानना है कि सख्त एंव जो लड़ाई लड़कर ही इस पर काबू पाया जा सकता है क्योंकि निश्चित तौर पर इन्हें फंडिंग, हथियार आदि की आपूर्ति पड़ौसी मुल्क के द्वारा ही की जाती है जिसकी हमेशा कोशिश रहती है कि किसी भी प्रकार भारत में दहशत का माहौल बनाया जाए। भारतीय युवा वर्ग को ड्रग्स, गैंगस्टर, सैक्स रैकेट आदि में लगाकर उन्हें गलत राह पर डाला जाए ताकि वह देश की तरक्की में योगदान ना दे पाएं। हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पंजाब मूल के 61 बड़े गैंगस्टरों में से 18 सीधे अमेरिका की सरजमीं से अपने आपराधिक नेटवर्क चला रहे हैं। यानी पंजाब में होने वाले कई कत्ल, फिरौती, धमकी और हथियार सप्लाई की डोर विदेशों से हिलाई जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका के बाद यूएई में 9, कनाडा और जर्मनी में 6-6, ब्रिटेन और यूरोप में 5-5, ऑस्ट्रेलिया व पुर्तगाल में 3-3, थाईलैंड और मलेशिया में 2 जबकि पाकिस्तान, इटली, ब्राजील और इंडोनेशिया में एक-एक गैंगस्टर बैठा है। यह अपराधी विदेश में सुरक्षित रहकर पंजाब में खौफ का कारोबार चला रहे हैं। इसी खतरे को तोड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने 72 घंटे का बड़ा अभियान चलाया, जिसमें 3,287 गैंग सहयोगियों को दबोचा गया। 21 गैंगस्टरों पर रेड कॉर्नर नोटिस पहले से जारी हैं। साथ ही विदेश में बैठे अपराधियों को पकड़ने के लिए ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्सट्राडिशन सेल बनाया गया है, ताकि दुनिया के किसी भी कोने से अपराधियों को घसीटकर लाया जा सके। आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2022 से अक्तूबर 2025 तक पंजाब में पुलिस और गैंगों के बीच 324 मुठभेड़ें हुईं, जिनमें 24 गैंगस्टर मारे गए, 515 गिरफ्तार हुए, 319 घायल हुए और तीन पुलिसकर्मी शहीद हुए। यह साफ दिखाता है कि पंजाब में गैंगवार कितना खतरनाक रूप ले चुका है।

युवा वर्ग में बेचैनी की वजह?

संसद के बजट सत्र का प्रारम्भ राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों के संयुक्त उद्बोधन से हो चुका है और दूसरी तरफ देश में युवा वर्ग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए लाई गई नियमावली के विरुद्ध सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। इससे पता चलता है कि विभिन्न क्षेत्रों में सतत् विकास पथ पर आगे बढ़ते भारत में सामाजिक स्तर पर उस भाईचारे का माहौल नहीं है जो किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी शर्त होता है। यदि देश का युवा वर्ग सड़कों पर होगा तो भारत किस प्रकार अपना चहुंमुखी विकास कर पायेगा और नई पीढ़ियां किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर सकेंगी। विगत 13 जनवरी को जारी नई नियमावली में आयोग ने स्पष्ट किया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में यदि जातिगत आधार पर अनुसूचित जातियों, जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो इसे गंभीर आपराधिक श्रेणी में रखा जायेगा और ऐसे कृत्य के खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई की जायेगी। इस मामले में सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि भेदभाव के लिए समाज के कथित सवर्ण समाज से आने वाले छात्रों को पहले से ही उत्पीड़क मान लिया गया है क्योंकि नियम में यह नहीं कहा गया है कि किसी भी जाति या वर्ग के छात्र के खिलाफ किये गये भेदभाव को आपराधिक कृत्य की श्रेणी में डाला जायेगा। जाहिर है कि इसे लेकर युवा समाज में बेचैनी होनी ही थी क्योंकि नियम एक पक्षीय है और समाज के एक वर्ग से आने वाले छात्रों को पहले से ही शक की नजर से देखता है। इस निमावली के विरुद्ध देश के सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिका दाखिल हो चुकी है। अतः पूरा मामला न्यायिक समीक्षा के दायरे में भी जा सकता है। नई नियमावली के अनुसार प्रत्येक शिक्षण संस्थान में एक समानता समिति का गठन भी किया जायेगा जो भेदभाव की शिकायतों को सुनकर आवश्यक आगे की कार्रवाई करेगी। इस समिति के संरक्षक विश्वविद्यालय के कुलपति या सर्वोच्च प्रशासक होंगे। समिति में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा। नियमावली में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि यदि किसी शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी या गलत पाई जाती है तो उसके विरुद्ध समुचित दंड की क्या व्यवस्था होगी। युवा वर्ग में इस उपनियम के न होने से भी भारी रोष व्याप्त है और उसका मानना है कि इसके न होने से विश्वविद्यालय जातिगत राजनीति का अखाड़ा बन जायेंगे और यहां भी वोटबैंक की राजनीति का बोलबाला हो जायेगा। इस पर यदि गौर किया जाये तो उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए निश्चित तौर पर यह बहुत गंभीर स्थिति होगी मगर दूसरी तरफ यह भी हकीकत है कि 2019 में दक्षिण के एक विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला नाम के दलित छात्र ने अपने साथ विश्वविद्यालय में हुए जातिगत भेदभाव के चलते ही आत्महत्या कर ली थी। यह मामला भी सर्वोच्च न्यायालय में गया जो कि अभी तक जारी है। इस मामले की सुनवाई करते हुए ही न्यायालय ने निर्देश दिया था कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में सामाजिक न्याय तन्त्र कड़ा किया जाये। इस निर्देश को ध्यान में रखते हुए ही केन्द्र सरकार ने नई नियमावली का गठन किया परन्तु वह इसे सन्तुलित नहीं रख सकी। अब शिक्षा मन्त्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान कह रहे हैं कि समाज के किसी भी वर्ग के छात्र के खिलाफ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जायेगा किन्तु प्रश्न यह है कि जब नियमावली यह चीख-चीख कर कह रही है कि केवल अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग के खिलाफ आने वाली शिकायतों को ही सुना जायेगा तो प्राकृतिक न्याय किस प्रकार हो पायेगा? हालांकि संभावित पीड़ित वर्ग समूह में दिव्यांग, महिला, नस्ल व क्षेत्र आदि को भी शामिल किया गया है मगर मुख्य मामला जातिगत भेदभाव का ही है। मैंने इस मामले में दो दिन पहले भी लिखा था कि अनुसूचित जातियों व जनजातियों के साथ अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों को जोड़ना गैर तार्किक था और भारत की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक मान्यताओं के प्रतिकूल था मगर यह कार्य 2012 में ही हो चुका था। अब सवाल यह है कि हम परिस्थितियों को किस प्रकार सर्व सामाजिक हित में बनायें जिससे सामाजिक न्याय भी हो सके और भारत की नई पीढ़ियां जातिवाद के जहर से निजात भी पा सकें। निश्चित रूप से इस सामाजिक वर्जना से शिक्षा के प्रचार-प्रसार द्वारा ही निजात पाया जा सकता है क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाती है और उसे रूढ़िवादिता के विरुद्ध तैयार करते हुए वैज्ञानिक सोच का सृजन करती है मगर जब शिक्षण संस्थान स्वयं जातिगत भावना से ग्रस्त हो जायेंगे तो हम किस दरवाजे पर सामाजिक न्याय की भीख मांगने जायेंगे? इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने विश्वविद्यालयों को जातिगत राजनीति के अखाड़े से दूर रखें। इसके लिए हमें विश्वविद्यालयों में ऐसा वातावरण बनाना होगा जिससे युवा पीढ़ियां जातिगत विद्वेष की शिकार न बन सकें। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि झूठी या बदले की भावना से की गई शिकायत करने वाले लोगों के खिलाफ भी समुचित कार्रवाई की जाये। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान समय में जिस तरह की गला काट प्रतियोगिता चल रही है उसके चलते पहले से ही छात्रों के बीच वह सौहार्दता का माहौल नहीं बचा है जिसकी कल्पना पिछले दशकों में की जा सकती थी। इसके साथ ही उच्च शिक्षा पर जिस तरह धनतन्त्र का कब्जा होता जा रहा है उससे देश का 90 प्रतिशत समाज त्रस्त है ऐसे में यदि हम अपने विश्वविद्यालयों को जातिगत राजनीति का अखाड़ा बना देंगे तो आने वाले समय में भारत के सम्पूर्ण विकास के ढांचे पर कुप्रभाव पड़ेगा। अतः शिक्षा मन्त्री श्री प्रधान को इस बारे में जल्दी ही कारगर कदम उठाना चाहिए और युवा पीढ़ी को उज्ज्वल भविष्य के प्रति आश्वस्त इस प्रकार करना चाहिए कि सामाजिक न्याय सभी वर्गों के छात्रों के साथ हो सके।

सम्पादकीय...

यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी

भारत -यूरोपीय संघ (ई.यू.) संबंधों में एक ऐतिहासिक मोड़ तब आया, जब नई दिल्ली में हुई भारत-ई.यू. समिट के दौरान दोनों पक्षों के बीच एक अहम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफ.टी.ए.) पर बातचीत पूरी होने की औपचारिक घोषणा की गई, जिसमें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यह पूरा घटनाक्रम इस बात को साफ तौर पर दिखाता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतन्त्र भारत और दुनिया के सबसे बड़े एकल बाजार यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और गहरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एफ.टी.ए. को एक संतुलित और भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया समझौता बताया, जो व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को नई रफ्तार देगा। उन्होंने इसे भारत के युवाओं के लिए नए अवसरों से जोड़ा, खासतौर पर व्यापार और मोबिलिटी से जुड़े समझौतों के जरिए और कहा कि आज दुनिया में भारत पर बढ़ते भरोसे के चलते ऐसे समझौते नई संभावनाएं खोल रहे हैं। यह समझौता मोदी सरकार के उस विजन के अनुरूप है, जिसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाते हुए भी वैश्विक अर्थव्यवस्था से मजबूती से जोड़ा गया है। इस एफ.टी.ए. को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा और यही बात यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भी दोहराई। यह समझौता मुख्य रूप से वस्तुओं, सेवाओं और व्यापार नियमों पर केंद्रित है, जबकि निवेश संरक्षण और भौगोलिक संकेतकों (ज्योग्राफिकल इंडिकेशन्स) के लिए अलग-अलग ढांचे तय किए गए हैं। इस समझौते के तहत भारत और ई.यू. के बीच होने वाले 90 प्रतिशत से अधिक व्यापारिक सामानों पर टैरिफ को कम करने या पूरी तरह खत्म करने का प्रावधान है। भारत के लिए यह समझौता खास तौर पर उन श्रम-आधारित निर्यात क्षेत्रों को बड़ा फायदा देगा, जिनमें कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट्स, केमिकल्स, रत्न एवं आभूषण, चमड़ा, जूते-चप्पल, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रिकल मशीनरी शामिल हैं- इन उत्पादों को ई.यू. बाजार में शुल्क-मुक्त या रियायती पहुंच मिलेगी। वहीं यूरोपीय संघ के लिए, इस समझौते के तहत ऑटोमोबाइल्स, वाइन, स्पिरिट्स और अन्य उत्पादों पर चरणबद्ध तरीके से टैरिफ कम किए जाएंगे। भारत की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को इस समझौते में संरक्षण दिया गया है। सेवाओं के क्षेत्र में टेलीकम्युनिकेशन, परिवहन, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जैसे सैक्टर्स को खोलने का प्रावधान है। भारत के लिए, यह समझौता वैश्विक स्तर पर बढ़ते संरक्षणवाद और अन्य देशों द्वारा लगाए जा रहे ऊंचे टैरिफ के दबाव को भी संतुलित करेगा। इस समझौते से भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, निवेश आकर्षित होगा, भारत यूरोपीय सप्लाई चेन का और मजबूत हिस्सा बनेगा और मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग को नई ताकत मिलेगी। वहीं यूरोपीय संघ के लिए यह 1.4 अरब उपभोक्ताओं वाले विशाल भारतीय बाजार के दरवाजे खोलना है।

नेतृत्व में दूरदर्शिता और उदारता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नबीन को अपना बॉस कहा है। भाजपा में कौन 'बॉस' है यह सब जानते है, पर यह तो मानना पड़ेगा कि 45 वर्ष के नितिन नबीन को अध्यक्ष बना कर भाजपा के हाईकमान ने एक बार फिर प्रदर्शित कर दिया कि वह लगातार पार्टी का नवीनीकरण करते जाते हैं। पार्टी पुराने घिसे-पिटे नेताओं के बल पर आश्रित नहीं रहती, जैसे कांग्रेस है या कई प्रादेशिक पारिवारिक पार्टियां हैं। झोले से अचानक ऐसा नाम निकाला जाता है कि लोग दंग रह जाते हैं। वह पांच बार विधायक चुने जा चुके हैं और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं। उनके चुनाव से संदेश है कि भाजपा मैरिट को डाइनेस्टी पर तरजीह देती है। हरियाणा, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड,दिल्ली जैसे प्रदेशों में पहले ही भाजपा नए चेहरे प्रस्तुत कर चुकी है। सब सफल नहीं हैं, पर संदेश तो है कि पार्टी किसी परिवार की जागीर नहीं है। नितिन नबीन के आगे भी बहुत चुनौती है। केरल, असम, बंगाल, पुडुचेरी और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव जीतने हैं। बंगाल और तमिलनाडु में स्थानीय भावनाओं से जूझना है। केरल में कुछ प्रगति हुई है पर पैर नहीं जमे जबकि असम में दस साल के बाद भाजपा सरकार को एंटी-इंकमबंसी, शासन विरोधी भावना, का सामना करना पड़ सकता है। नितिन नबीन ने अपने बिहार में देखा होगा कि चाहे अच्छे बहुमत से सरकार बन गई है, पर आंकड़े बहुत संतोषजनक नहीं हैं। राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा का वोट लगभग उतना ही है जितना पिछली बार था। राजद को 23फीसदी तो भाजपा को 20फीसदी। सरकार बनी तो नीतीश कुमार की जदयू और दूसरी छोटी पार्टियों के समर्थन से। चुनाव से पहले महिलाओं को 10000 रुपए खाते में डालना भी बताता है कि पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले ईडी की चहलकदमी भी बताती है कि कहीं आत्मविश्वास की कमी है। बिहार चुनाव एक बात और प्रदर्शित कर गए कि कभी सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस का भी कुछ सुधार नहीं रहा। वह 61 सीटें लड़े और केवल 6 में विजय हुए। आखिर तक वह फैसला नहीं कर सके कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना है कि नहीं? सब निर्णय राहुल गांधी और उनकी मंडली लेती है जिस तक पहुंचना सबके लिए आसान नहीं है। पिछले साल दिसम्बर में उड़ीसा से कांग्रेस के पूर्व विधायक मुहम्मद मकूम ने सोनिया गांधी को पत्र लिख कर शिकायत की थी कि बार बार प्रार्थना करने के बावजूद उन्हें तीन साल राहुल गांधी से मिलने का समय नहीं दिया गया। उनकी शिकायत है कि नेतृत्व और आम कार्यकर्ता के बीच संवाद नहीं है। उड़ीसा में पार्टी छह बार लगातार हार चुकी है, पर फिर भी राहुल गांधी के पास पूर्व विधायक को मिलने का समय नहीं था। राहुल गांधी के बारे यह शिकायत कई नेता कर चुके हैं। गुलाम नबी आज़ाद, पृथ्वी राज चौहान, शशि थरूर सब राहुल गांधी के व्यवहार से आहत हैं। आज़ाद तो पार्टी ही छोड़ गए। असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा सरमा ने बताया था कि जब वह कांग्रेस में थे और राहुल गांधी को मिलने गए तो राहुल उनसे बात करने की जगह अपने कुत्ते से खेलते रहे। सरमा 22 वर्ष के बाद कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में चले गए जहां असम में मुख्यमंत्री बन उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी के क्षेत्र से पैर ही उखाड़ दिए। राहुल का बार-बार विदेश चले जाना भी बताता है कि वह फुल टाइम राजनेता नहीं है और शायद न ही बनना चाहते हैं। उनके चरित्र में भी अजब विरोधाभास है।

एक तरफ वह साथियों से दूर रहते हैं तो दूसरी तरफ आम लोगों में घुलमिल जाते हैं जैसा हमने उनकी दो यात्राओं में देखा था। अब भी वह इंदौर में उन परिवारों के मिलने पहुंच गए जिनके प्रियजन ज़हरीला पानी पीने से मारे गए थे। यह व्यक्तिगत संवेदनशीलता दिखाता है, पर राजनेता के तौर पर वह बार-बार असफल हो रहे हैं। कोई भी तीर निशाने पर नहीं पड़ रहा। वह होमवर्क करते हैं। मुद्दे उठाते हैं, पर कहीं लोगों के साथ 'डिस्कनेक्ट' है जिसकी मुहम्मद मकूम ने भी शिकायत की थी। इस समय कांग्रेस केवल तीन प्रदेशों, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में अपने बल पर सत्ता में है। महाराष्ट्र के स्थानीय चुनावों में कांग्रेस 3/4 स्थान पर रही है। इलाज क्या है? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस में नई जान फूंक सकती हैं? हाल ही में प्रियंका गांधी को लेकर अंग्रेज़ी का शब्द 'बज़' बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। अर्थात उनको लेकर कोलाहल बहुत है। विशेष तौर पर जिस तरह संसद में प्रियंका ने वंदे मातरम् और मनरेगा को लेकर भाषण दिए, उसे लेकर बहुत चर्चा रही है। वह सहज हैं। अपनी बात कहते वक्त कटुता का इस्तेमाल नहीं करतीं जैसी कई बार राहुल गांधी के भाषणों में नज़र आती है। राहुल वन-ट्रैक हैं। अड़ गए तो अड़ गए। बार-बार देश की अर्थव्यवस्था को "डैड इकानिमी" कह रहे हैं। क्या मतलब है? शब्दों से कई बार दूसरों के प्रति नफ़रत भी टपकती है। दूसरी तरफ़ प्रियंका है जो स्पष्ट बात कहते हुए भी मर्यादा को कभी पार नहीं करतीं। हिन्दी पर भी अधिक अधिकार है। संसद में उनकी भाषण शैली को देखकर यह मांग बढ़ रही है कि पार्टी में उनकी भूमिका बढ़ाई जाए। कई वर्ष पहले एक मुलाक़ात में लालकृष्ण अडवाणी ने प्रियंका गांधी के बारे मेरे सवाल के जवाब में कहा था कि हां, वह एक चुनाव जीत सकती हैं-। उस समय बहुत चर्चा थी कि शक्ल, हावभाव इंदिरा गांधी जैसा है।

उन्हें कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड या ब्रह्मास्त्र समझा गया। पर प्रियंका की राजनीति में शुरुआत अच्छी नहीं रही। 2020 में उन्हें उत्तर प्रदेश का महासचिव बनाया गया। 'लड़की हूं लड़ सकती हूं' का नारा उन्होंने दिया, पर वह शानदार तरीक़े से असफल रही। बाद में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट स्ट्राइक ने कांग्रेस का सफ़ाया कर दिया

। केवल सोनिया गांधी रायबरेली जीत सकीं। राहुल गांधी खुद अमेठी हार गए। प्रियंका गांधी ने भी उत्तर प्रदेश से किनारा कर लिया और अब केरल में वायनाड से सांसद हैं। लेकिन अब बदलाव आया है। हम प्रियंका गांधी का संस्करण-2 देख रहे हैं। वह पहले से अधिक मैच्योर है, अधिक विश्वस्त नज़र आती है, खुद को अच्छा सांसद भी साबित कर रही हैं और अपनी ज़िम्मेदारी अच्छी तरह से निभाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की समस्या अधिक मूलभूत है। कांग्रेस अभी भी एक सामंती पार्टी है जिसे एक परिवार चला रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो केवल दिखावा है पार्टी के सभी निर्णय, ग़लत-सही, राहुल गांधी लेते हैं। नेतृत्व पुराने चले हुए वफ़ादार कारतूसों के बीच खुश नज़र आता है। भाजपा ने नई पीढ़ी को आगे कर दिया, पर कांग्रेस बदलने को तैयार नहीं। उदयपुर के चिन्तन शिविर में फ़ैसला लिया गया कि कार्यकारिणी में कम से कम आधे लोग युवा होंगे। पर आज भी 85 सदस्यों वाली कार्यकारिणी में केवल 12 ही 50 साल से कम उम्र के हैं। इसी का परिणाम है कि कभी सचिन पायलट नाराज़ हो जाते हैं तो आजकल शशि थरूर बिदक रहे हैं। जो युवा प्रतिभाशाली हैं वह समझ गए हैं कि राहुल के कारण उनका ऊपर का रास्ता बंद है। इसलिए हताशा बढ़ रही है। कई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह पार्टी ही छोड़ गए हैं। कांग्रेस के पतन का एक कारण ज़रूरत से अधिक केन्द्रीयकरण है। भाजपा भी अब काडर-बेस्ड पार्टी की जगह पर्सनैलिटी-बेस्ड पार्टी बनती जा रही है, पर वहां यह ढका है क्योंकि नेतृत्व चुनाव जीतने की क्षमता रखता है। कांग्रेस में संगठन को चुस्त बनाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। राहुल गांधी का कहना है कि -कांग्रेस केवल एक राजनीतिक दल नहीं है, भारत की आत्मा की आवाज़ है। खड़गे जी का कहना है कि कांग्रेस एक विचारधारा है और विचारधारा कभी नहीं मरती। यह सज्जन किस ग़लत फ़हमी में है जब पार्टी एक परिवार के इर्द-गिर्द लिपट गई तो विचारधारा कहां बची? परिवार का हित पार्टी का हित बन गया। स्थानीय नेतृत्व को उभरने नहीं दिया जाता। जदयू के सांसद मनोज झा ने बहुत सही बात कही है, हमारे पास चुनाव की आज़ादी तो है, पर कोई अर्थपूर्ण विकल्प नहीं है। अपनी लाख कमज़ोरियों के बावजूद इस विकल्प का केन्द्र कांग्रेस ही हो सकती है। पर विपक्ष को साथ लेने के लिए नेतृत्व में दूरदर्शिता और उदारता चाहिए जो राहुल गांधी की कांग्रेस में नज़र नहीं आ रही। इसीलिए भी प्रियंका गांधी की चर्चा अधिक हो रही है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने तो मांग भी की है कि प्रियंका को पार्टी की बागडोर सम्भाल दी जाए। बहुत और नेता भी यह महसूस करते हैं, पर चुप हैं। जिस तरह राहुल अचानक गायब हो जाते हैं उससे प्रियंका की मांग और बढ़ गई है। लोग राहुल गांधी के नेतृत्व से ऊब गए हैं। वह नया चेहरा और नई सोच चाहते हैं। क्योंकि पार्टी ने परिवार के इर्द-गिर्द ही घूमना है इसलिए यह चेहरा प्रियंका ही हो सकती हैं। उन्हें नेतृत्व का मौक़ा मिलना चाहिए, पर क्या मिलेगा? सोनिया गांधी मानेंगी? आने वाले विधानसभा चुनावों में केरल से सांसद प्रियंका को केरल की जगह दूर असम का प्रभारी बना दिया गया है। क्या संदेश है ?

प्रशासन और राजनीतिक संतुलन में एक बड़ा रिक्त स्थान

यह खबर केवल एक व्यक्ति के निधन की नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के एक पूरे युग के अचानक थम जाने की सूचना है। 28 जनवरी 2026 की सुबह जब बारामती में हुए विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित अनंतराव पवार के असामयिक निधन की पुष्टि हुई, तो वह क्षण केवल पवार परिवार के लिए नहीं, बल्कि समूचे महाराष्ट्र और देश की राजनीति के लिए गहरे शोक और स्तब्धता का कारण बन गया। जिस नेता को लोग अधिकार, अनुभव और निर्णय क्षमता का पर्याय मानते थे, उसका इस तरह अचानक चले जाना सत्ता, प्रशासन और राजनीतिक संतुलन में एक बड़ा रिक्त स्थान छोड़ गया है। एक संभावनाओं भरी महाराष्ट्र की राजनीति एवं राष्ट्रीय विचारों का सफर ठहर गया, उनका निधन न केवल महाराष्ट्र के लिये, भारत की राष्ट्रवादी सोच के लिये बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रवादी राजनीति पर एक गहरा आघात है, अपूरणीय क्षति है। उनके निधन से सहकारी आन्दोलन को भी गहरा धक्का लगा है। अजित पवार का जीवन किसी राजसी विरासत की सहज कहानी नहीं था। 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देओली प्रवरा क्षेत्र में जन्मे अजित पवार ने जीवन को बहुत करीब से संघर्ष करते हुए देखा। उनके पिता अनंतराव पवार फिल्म जगत से जुड़े रहे, राजकमल स्टूडियो में काम किया, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां साधारण रहीं। औपचारिक शिक्षा माध्यमिक स्तर तक ही सीमित रही, किंतु जीवन की व्यावहारिक पाठशाला ने उन्हें वह सिखाया जो बड़े-बड़े शैक्षणिक संस्थान भी नहीं सिखा पाते। शायद यही कारण रहा कि अजित पवार की राजनीति किताबों से नहीं, जमीन से निकली हुई राजनीति थी, जिसमें किसानों की पीड़ा, सहकारी संस्थाओं की ताकत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नब्ज साफ दिखाई देती थी। राजनीति में उनका प्रवेश किसी बड़े मंच से नहीं, बल्कि सहकारी आंदोलन की प्रयोगशाला से हुआ। 1982 में मात्र बीस वर्ष की आयु में उन्होंने एक चीनी सहकारी संस्था का चुनाव लड़ा। यह वही दौर था जब महाराष्ट्र की राजनीति में सहकारी संस्थाएं सत्ता की रीढ़ मानी जाती थीं। अजित पवार ने बहुत जल्दी समझ लिया कि यदि ग्रामीण महाराष्ट्र को साधना है तो उसे बैंक, चीनी मिल, सिंचाई और बिजली से जोड़ना होगा। यही समझ आगे चलकर उनकी राजनीतिक पहचान की सबसे बड़ी ताकत बनी। 1991 अजित पवार के राजनीतिक जीवन का निर्णायक वर्ष रहा। पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बनने के साथ ही उन्होंने वित्तीय प्रशासन और संगठन संचालन में अपनी दक्षता का परिचय दिया। सोलह वर्षों तक इस पद पर बने रहना अपने आप में उनकी विश्वसनीयता और पकड़ को दर्शाता है। उसी वर्ष बारामती से लोकसभा के लिए निर्वाचित होना उनके बढ़ते कद का प्रमाण था, लेकिन उन्होंने यह सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए छोड़ दी। यह फैसला केवल पारिवारिक निष्ठा का नहीं, बल्कि राजनीतिक दूरदृष्टि का भी उदाहरण था। इसके बाद विधानसभा में प्रवेश और फिर लगातार बारामती से जीत ने उन्हें जनाधार का वह आधार दिया, जिसे महाराष्ट्र की राजनीति में विरले ही कोई चुनौती दे सका। अजित पवार को सत्ता के गलियारों में पहुंचाने वाली सबसे बड़ी विशेषता उनकी प्रशासनिक पकड़ थी। कृषि, बागवानी, बिजली और जल संसाधन जैसे कठिन और संवेदनशील विभागों को संभालते हुए उन्होंने विकास और विवाद दोनों को नजदीक से जिया। जल संसाधन मंत्री के रूप में कृष्णा घाटी और कोकण सिंचाई परियोजनाओं से उनका नाम जुड़ा। इन परियोजनाओं ने जहां किसानों के लिए पानी और उम्मीद का संदेश दिया, वहीं आलोचनाओं और आरोपों का बोझ भी उनके कंधों पर रखा। इसके बावजूद वे उन नेताओं में रहे जो फाइलों से नहीं, फैसलों से पहचाने जाते थे। उपमुख्यमंत्री के रूप में उनका सफर महाराष्ट्र की राजनीति में एक अनोखा अध्याय है। छह बार इस पद तक पहुंचना केवल राजनीतिक संयोग नहीं था, बल्कि सत्ता संतुलन, गठबंधन राजनीति और संगठनात्मक ताकत का परिणाम था। वे सरकार में अक्सर संकटमोचक की भूमिका में दिखे। बजट, वित्तीय प्रबंधन और संसदीय रणनीति में उनकी पकड़ ऐसी थी कि विरोधी भी उनके अनुभव को नजरअंदाज नहीं कर पाते थे। उन्हें महत्वाकांक्षी कहा गया, कभी-कभी कठोर और रूखे स्वभाव का नेता भी बताया गया, लेकिन यह भी सच है कि सत्ता की वास्तविकता को वे भावनाओं से नहीं, निर्णयों से देखते थे। विवाद उनके राजनीतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा रहे। सिंचाई घोटाले से लेकर बयानबाजी तक, कई मौके ऐसे आए जब उनकी छवि पर प्रश्नचिह्न लगे। अगर बांध में पानी नहीं है तो क्या पेशाब करके भरें? जैसे बयान ने उन्हें आलोचनाओं के केंद्र में ला खड़ा किया। उन्होंने माफी भी मांगी, सफाई भी दी और समय के साथ उन विवादों से उबरते हुए फिर सत्ता के शीर्ष पर लौटे। यह उनकी राजनीतिक जिजीविषा का प्रमाण था कि आलोचना और आरोप उन्हें रोक नहीं पाए। शरद पवार के साथ उनके रिश्ते को लेकर भी हमेशा चर्चाएं रहीं। कभी मतभेद, कभी दूरी और कभी सियासी अलग राह की अटकलें। लेकिन अजित पवार स्वयं को हमेशा शरद पवार का अनुयायी बताते रहे। उन्हें मिला «दादा» का संबोधन केवल पारिवारिक नहीं था, बल्कि वह एक राजनीतिक ब्रांड बन चुका था, जो उनके समर्थकों में भरोसे और नेतृत्व की भावना जगाता था। वे संगठनकर्ता भी थे और प्रशासक भी, रणनीतिकार भी और जमीनी नेता भी। उन्हें अपनी विविध आयामी भूमिकाओं से अपने को मिले 'दादा' के अलंकरण को सार्थक भी किया और जीवंतता भी दी। उनका असामयिक निधन एक क्रूर विडंबना है। जिस नेता ने दशकों तक सत्ता की उड़ान भरी, उसकी जीवन यात्रा एक विमान हादसे में थम गई। कहा जाता है कि दुर्घटना से कुछ समय पहले तक वे पूरी तरह सक्रिय थे, योजनाओं, बैठकों और राजनीतिक समीकरणों में व्यस्त। यह अचानक आई मृत्यु उस अनिश्चितता को रेखांकित करती है, जो सत्ता और जीवन दोनों के साथ जुड़ी है। अजित पवार का व्यक्तित्व एवं कृतित्व सफल राजनेता, समाज निर्माता, ग्राम-उद्धारक, सहकारी आन्दोलन पुरोधा, कुशल प्रशासक के रूप में अनेक छवि, अनेक रंग, अनेक रूप में उभरकर सामने आता है। आपके जीवन की दिशाएं विविध एवं बहुआयामी थीं। आपके जीवन की धारा एक दिशा में प्रवाहित नहीं हुई, बल्कि जीवन की विविध दिशाओं का स्पर्श किया। यही कारण है कि कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र आपके जीवन से अछूता रहा हो, संभव नहीं लगता। आपके जीवन की खिड़कियाँ समाज एवं राष्ट्र को नई दृष्टि देने के लिए सदैव खुली रहीं। उनकी सहजता और सरलता में गोता लगाने से ज्ञात होता है कि वे राजनीतिक सरोकार से ओतप्रोत एक अलहद एवं साहसिक व्यक्तित्व थे। बेशक अजित पवार अब इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन अपने जुझारू राजनीति जीवन के दम पर वे हमेशा भारतीय राजनीति एवं राष्ट्रवादी सोच के आसमान में एक सितारे की तरह टिमटिमाते रहेंगे। आज जब महाराष्ट्र और देश उनके निधन पर शोकाकुल है, तब अजित पवार का मूल्यांकन केवल प्रशंसा या आलोचना के तराजू पर नहीं किया जा सकता। वे विवादों से घिरे रहे, लेकिन उनसे परिभाषित नहीं हुए। उनकी राजनीति कठोर थी, लेकिन उसमें अनुभव की गहराई थी। वे लोकप्रियता से अधिक प्रभाव में विश्वास रखते थे। शायद यही कारण है कि उनके जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा सन्नाटा है, जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। अजित पवार का जीवन यह सिखाता है कि राजनीति केवल भाषणों और नारों से नहीं चलती, बल्कि निर्णय, जोखिम और जिम्मेदारी से चलती है। उनका जाना एक चेतावनी भी है और एक स्मृति भी, क्योंकि सत्ता क्षणभंगुर है, लेकिन अनुभव और प्रभाव लंबे समय तक याद किए जाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में «दादा» के नाम से पहचाना जाने वाला यह व्यक्तित्व अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है, लेकिन उसकी छाया आने वाले वर्षों तक राज्य की राजनीति पर बनी रहेगी।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कल्पना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/00882)

सीयूजी नंबर न उठाने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई : कमिश्नर

मुरादाबाद।

विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक में लापरवाह अफसरों की लगाई क्लास

मंडल में अधिकारियों द्वारा सीयूजी नम्बर पर आने वाली फोन कॉल को रिसीव न करना तथा अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा समय पर कार्यालयों में न पहुंचने की शिकायतों पर कठोरतम कार्यवाही के निर्देश मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह ने दिए हैं। आयुक्त सभागार में आयोजित विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि आमजन को विभागीय सेवाओं और योजनाओं से जोड़ने तथा शासन दे निर्देशों के गंभीरतापूर्वक क्रियान्वयन में लापरवाही किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं होगी। मंडल में उपलब्ध 108 और 102 एंबुलेंस सेवाओं की समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि रिस्पॉन्स टाइमिंग मानक के अनुरूप हो साथ ही एंबुलेंस में उपलब्ध संसाधनों की क्रियाशीलता भी अनिवार्य रूप से हो ताकि मरीजों को समय पर जरूरी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होने में कोई समस्या उत्पन्न न हो। विद्युत कनेक्शनों की क्षमता बढ़वाने और विद्युत बिलों का भुगतान करने के दौरान उपभोक्ताओं को दिक्कतें न आए इसके लिए उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए साथ ही कहा कि झुके विद्युत पोल भी

दुरुस्त कराए जाएं ताकि कोई दुर्घटना न होने पाए। मंडल में 128 ग्राम प्रधानों के विरुद्ध प्रचलित जांच प्रक्रिया में भी मंडलायुक्त ने तेजी लाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के साथ ही फीडबैक प्राप्त करने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया। फार्मर रजिस्ट्री में सम्भल और मुरादाबाद की धीमी प्रगति पर उन्होंने कहा कि 01 सप्ताह के भीतर मंडल के सभी जिलों की प्रगति में सुधार हो जाना चाहिए। वर्षा जल संचयन हेतु संचालित खेत तालाब योजना के अंतर्गत मुरादाबाद और रामपुर में धीमी प्रगति पर भी उन्होंने नाराजगी जताई और विभागीय अधिकारियों से कारणों के बारे में पूंछा। कीटनाशी बिक्री केंद्रों पर कीटनाशी रसायनों के गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान बिजनौर और अमरोहा में कुल प्राप्त किए गए नमूनों के सापेक्ष खराब कार्यवाही प्रगति पर भी उन्होंने कारणों के बारे में जानकारी ली। नगरीय क्षेत्रों में फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की समस्या पर प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है, मंडलायुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया। बिजनौर में कॉन्ट्रेक्ट आधार पर तैनात महिला चिकित्साधिकारी को सीएमओ बिजनौर द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से मातृत्व अवकाश प्रदान करने के प्रकरण में मंडलायुक्त ने सीएमओ बिजनौर को स्पष्टीकरण नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने एनआरएलएम, मुख्यमंत्री आवास योजना, मनरेगा अमृत सरोवर 2.0, आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण, सोशल ऑडिट, मॉडल शॉप, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, छात्रवृत्ति योजना आदि की प्रगति को लेकर भी विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर जिलाधिकारी मुरादाबाद अनुज सिंह, जिलाधिकारी रामपुर अजय कुमार द्विवेदी, जिलाधिकारी बिजनौर जसजीत कौर, जिलाधिकारी सम्भल राजेंद्र पैंसिया, जिलाधिकारी अमरोहा श्रीमती निधि गुप्ता वत्स सहित समस्त सीडीओ एवं अन्य संबंधित अधिकारी गण मौजूद रहे।

सैनिकों के पराक्रम, त्याग और समर्पण को किया याद

मुरादाबाद।

पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह

मधुरम हेरिटेज दिल्ली रोड पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय मुरादाबाद के तत्वाधान पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह मुख्य अतिथि एवं उत्तर प्रदेश के सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशक ब्रिगेडियर अतुल कुमार सेना मेडल (सेवानिवृत) और मेजर जनरल अमिताभ जोशी (सेवानिवृत) विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में सैकड़ों की संख्या में भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों ने भाग लिया।

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कमांडर ज्ञान स्वरुप (सेवानिवृत) ने मुख्य अतिथि एवं अन्य अथितियों का स्वागत किया। अपने संबोधन में कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने कहा कि यह आयोजन केवल पुनर्मिलन नहीं, बल्कि उन सैनिकों के पराक्रम, त्याग और समर्पण को याद करने का अवसर है जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने पूर्व सैनिकों को केंद्र और रा'य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। मुरादाबाद के सैनिक इतिहास का उल्लेख करते हुए उन्होंने आगे कहा कि यहां के पूर्व सैनिक और वीर नारियाँ हमारी प्रेरणा हैं, और यह पुनर्मिलन नई पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति और त्याग के सर्वो'च उदाहरण के रूप में सैनिक जीवन का संदेश देता है। सैनिकों की बदौलत देश सुरक्षित है। जान जोखिम में डालकर देश और नागरिकों की सुरक्षा में सीमा पर डटे रहते हैं। एक सैनिक अपनी नौकरी का पूरा कार्यकाल देश की प्रतिष्ठा व मन सम्मान के लिए न्योछावर कर देते हैं। विधायक ने कहा कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पूर्व सैनिकों के मिलन समारोह में भाग लेने का मौका मिला।

यूजीसी कानून को लेकर सड़कों पर उतरा सवर्ण समाज

मुरादाबाद।

जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों को काला कानून बताते हुए गुरुवार को सम्पूर्ण सवर्ण समाज, क्षत्रिय महासभा, अग्रवाल महासभा, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा एवं स्वर्ण समाज के सैकड़ों लोगों ने अम्बेडकर पार्क, सिविल लाइंस में एकत्र होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सभा के बाद पदाधिकारी और कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया।

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने यूजीसी का काला कानून वापस लो सवर्ण छात्रों के साथ अन्याय बंद करो और शिक्षा में भेदभाव नहीं चलेगा जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि यूजीसी का नया नियम सवर्ण एवं सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है और शिक्षा संस्थानों में भय का माहौल पैदा कर रहा है। सभा को संबोधित करते हुए सवर्ण समाज के राष्ट्रीय महामंत्री संजीव आकांक्षी ने कहा कि बिना प्रमाण की शिकायतों के आधार पर सामान्य वर्ग के छात्रों को अपराधी की तरह देखना सरासर अन्याय है। रजत शर्मा ने कहा कि ये नियम संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं और शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। क्षत्रिय समाज से अमित ठाकुर ने आरोप लगाया कि यह नियम शिक्षा के क्षेत्र में जातिगत द्वेष और राजनीति को बढ़ावा दे रहा है, जबकि शिक्षा का मूल्यांकन योग्यता, परिश्रम और नैतिकता के आधार पर होना चाहिए। वहीं बार एसोसिएशन के सचिव कपिल गुप्ता ने कहा कि यदि शिकायत झूठी पाई जाती है, तो शिकायतकर्ता के विरुद्ध किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान न होना न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। वक्ताओं ने कहा कि नए नियमों के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को जाति आधारित भेदभाव की शिकायत पर विशेष संरक्षण दिया गया है, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों को बिना प्रमाण की शिकायतों पर भी कार्रवाई के खतरे में डाल दिया गया है। कई उ'च न्यायालय भी पूर्व में ऐसे कानूनों के दुरुपयोग पर टिप्पणी कर चुके हैं। सभा में मौजूद लोगों ने एक स्वर में चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर सरकार ने मांगों पर संज्ञान नहीं लिया, तो मुरादाबाद सहित पूरे प्रदेश में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान डॉ. प्रदीप शर्मा, आचार्य राजेश शर्मा, सुनील कुमार शर्मा, अनिमेष शर्मा, आदि मौजूद रहे।

संविधान को जानो विषय पर हुई क्विज़ प्रतियोगिता

मुरादाबाद।

टीम इंडिया के संयम जैन और पारस जैन को द्वितीय, जबकि टीम हिंदुस्तान के अनूप कुमार, रेशु शर्मा और कृष्णा वार्ष्णेय तृतीय स्थान पर रहे।

तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद के फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के फ्री थिंकर्स क्लब की ओर से अपने संविधान को जानो पर आयोजित क्विज प्रतियोगिता में टीम भारत के संजीव पाल और शिवम विजेता रहे। टीम इंडिया के संयम जैन और पारस जैन को द्वितीय, जबकि टीम हिंदुस्तान के अनूप कुमार, रेशु शर्मा और कृष्णा वार्ष्णेय तृतीय स्थान पर रहे। इससे पूर्व फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के डीन प्रो. राकेश कुमार द्विवेदी, सीसीएसआईटी के विभागाध्यक्ष प्रो. शंभु भारद्वाज, एडिशनल एचओडी डॉ. रूपल गुप्ता, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के फ्री थिंकर्स क्लब की कोऑर्डिनेटर डॉ. इंदु त्रिपाठी आदि ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्र+वलित करके प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया। डीन प्रो. द्विवेदी बोले, क्विज प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य स्टुडेंट्स में भारतीय संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाना, राष्ट्रप्रेम एवम् नागरिक चेतना की भावना को सुदृढ़ करना है। प्रतियोगिता के प्रारंभिक चरण में कुल 18 टीमों ने भाग लिया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद पांच टीमें- इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, भारतवर्ष और आर्यावर्त का चयन फाइनल राउंड के लिए हुआ। कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स की विभागाध्यक्षा डॉ. अलका वर्मा, सिविल इंजीनियरिंग के विभागाध्यक्ष डॉ. आशीष सिमाल्टी, सीआरसी हेड डॉ. संकल्प गोयल, डॉ. प्रियांक सिंघल, डॉ. पराग अग्रवाल, डॉ. संदीप वर्मा आदि मौजूद रहे। संचालन स्टुडेंट्स अंशिका ककड़ और कुमारी प्रियांशी ने किया।

रक्तदान मानवता की सबसे बड़ी सेवाः डॉ. काव्य सौरभ

मुरादाबाद। रोटरी क्लब मुरादाबाद ईस्ट द्वारा द रोटरी फाउंडेशन की ग्लोबल ग्रांट के अंतर्गत आयोजित रक्तदान जागरूकता अभियान का आयोजन गुरुवार को दिल्ली रोड स्थित राही होटल एंड बैंक्वेट्स में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी डॉ. काव्य सौरभ रस्तोगी उपस्थित रहे। आयोजन में लगभग 200 रोटेरियन सदस्यों , संगिनियों एवं युवाओं की सहभागिता रही। कार्यक्रम के दौरान रक्तदान जागरूकता पत्रक का विधिवत विमोचन मुख्य अतिथि डॉ. काव्य सौरभ रस्तोगी एवं अतिथियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट रोटरी फाउंडेशन चेयर एवं पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन ललित मोहन गुप्ता की उपस्थिति विशिष्ट अतिथि के रूप में रही। मुख्य अतिथि डॉ. काव्य सौरभ रस्तोगी ने अपने संबोधन में रक्तदान को मानवता की सबसे बड़ी सेवा बताते हुए युवाओं से आगे आकर नियमित रक्तदाता बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि युवा इस सेवा को जीवन का हिस्सा बना लें, तो किसी भी आपात स्थिति में रक्त की कमी नहीं होगी। उन्होंने रोटरी क्लब मुरादाबाद ईस्ट द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। इस अवसर पर डीआरएफसी ललित मोहन गुप्ता ने कहा कि रोटरी फाउंडेशन के ग्लोबल ग्रांट्स समाज में स्थायी और प्रभावी परिवर्तन लाने का सशक्त माध्यम हैं। उन्होंने रक्तदान जैसे अभियानों को समय की आवश्यकता बताते हुए क्लब के प्रयासों की सराहना की।डॉ ऋचा गर्ग ने रक्तदान के संबंध में अपना शोध प्रस्तुत किया। चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के कॉर्डिनेटर चंद्रशेखर ने संगिनियों से रक्तदान जागरूकता अभियान में जुटने की अपील की । समाजसेवी संजीव गोयल ने अपने रक्तदान के अनुभव साझा किए । वहीं सरदार गुरविंदर सिंह ने कविता के माध्यम से रक्तदान के लिए प्रेरित किया ।

समाजसेवी विवेक गोयल ने भी रक्तदान पर अपने अनुभव साझा किए । कार्यक्रम में क्रेस्ट हॉस्पिटल के सहयोग से निःशुल्क ब्लड ग्रुपिंग एवं हीमोग्लोबिन जांच की गई तथा ×0 युवक-युवतियों ने रक्तदान की शपथ ली, जिसे उपस्थितजनों ने करतल ध्वनि के साथ प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम की शुरुआत में क्लब अध्यक्ष रोटेरियन संजय किशोर ने सभी अतिथियों का स्वागत किया, जबकि कार्यक्रम के अंत में सचिव रोटेरियन विनय मेहरोत्रा ने सभी सहयोगी संस्थाओं, चिकित्सकीय टीम एवं उपस्थित जनसमूह के प्रति आभार व्यक्त किया।

दुर्गा फाउंडेशन द्वारा महिलाओं व श्रद्धालुओं को मिल रहा सुरक्षा और सम्मान का सहारा

प्रयागराज।

दुर्गा फाउंडेशन द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सुविधाओं को लेकर लगातार सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। समाजसेवा के क्षेत्र में सक्रिय यह संस्था महिला सशक्तिकरण और जनकल्याण को अपना मुख्य उद्देश्य मानकर कार्य कर रही है। फाउंडेशन की सचिव दुर्गावती ने बताया कि दुर्गा फाउंडेशन का लक्ष्य महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना, उन्हें जागरूक बनाना तथा आत्मनिर्भरता की दिशा में हर संभव सहयोग प्रदान करना है। सचिव दुर्गावती ने कहा कि वर्तमान समय में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से सशक्त करना बेहद आवश्यक है। इसी सोच के साथ दुर्गा फाउंडेशन द्वारा समय-समय पर महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और

सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही जरूरतमंद महिलाओं को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने बताया कि इन दिनों आयोजित मां मेले के दौरान भी दुर्गा फाउंडेशन पूरी सक्रियता के साथ सेवा कार्यों में जुटी हुई है। मेले में दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए फाउंडेशन के स्वयंसेवक लगातार निगरानी रख रहे हैं। श्रद्धालुओं को उचित मार्गदर्शन, प्राथमिक चिकित्सा, पानी और आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दुर्गा फाउंडेशन की सचिव दुर्गावती ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रद्धालुओं और महिलाओं का सम्मान करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। सेवा भाव के माध्यम से ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है।- उन्होंने यह भी कहा कि फाउंडेशन का हर सदस्य सेवा को ही अपना धर्म मानकर कार्य करता है और आगे भी इसी भावना के साथ समाजसेवा जारी रखी जाएगी। मां मेले में दुर्गा फाउंडेशन की सक्रिय भूमिका से श्रद्धालुओं में सुरक्षा और विश्वास का भाव देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने फाउंडेशन के इस प्रयास की खुलकर सराहना की है। लोगों का कहना है कि ऐसे सामाजिक संगठनों की उपस्थिति से न केवल महिलाओं को सुरक्षा का एहसास होता है, बल्कि समाज में सहयोग और संवेदनशीलता की भावना भी मजबूत होती है। दुर्गा फाउंडेशन ने यह संकल्प लिया है कि भविष्य में भी महिला सशक्तिकरण, जनसेवा और सामाजिक उत्थान के कार्य पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निरंतर किए जाते रहेंगे।

डंबल से मारा, दरवाजे पर सिर पटका, दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो की पति ने की हत्या, 4 महीने प्रेग्नेंट थी

नई दिल्ली। दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. आरोप है कि हरियाणा सोनीपत जिले की रहने वाली काजल नाम की एक महिला की उसके ही पति ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी. इस हत्याकांड में दहेज प्रताड़ना का दावा किया गया है. काजल दिल्ली पुलिस की SWAT कमांडो यूनिट में तैनात थी जबकि आरोपी पति अंकुर खुद रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर काम करता है और दिल्ली कैंट में पोस्टेड है. काजल गन्नौर के बड़ी गांव की रहने वाली थी और चार महीने प्रेग्नेंट थी. आरोप है कि उसके पति और ससुराल वालों ने मिलकर दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी. एक ओर काजल के घर वाले नन्हे मेहमान के आने का इंतजार कर रहे थे और आरोपी अंकुर ने उनसे उनकी बेटी भी छीन ली. काजल के परिवार वालों का कहना है कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने दो हत्याएं की हैं. एक काजल की और दूसरी उस 4 महीने के भ्रूण की. काजल का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया. काजल और पति अंकुर दिल्ली के द्वारका जिले के मोहन गार्डन थाना इलाके में रहते थे. पहले इस मामले में हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान काजल की मौत के बाद अब इसमें हत्या की धारा जोड़ दी गई. आरोपी पति को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है. जानकारी के मुताबिक, 27 साल की काजल ने साल 2022 में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था. यहीं पर उसकी मुलाकात गन्नौर के रहने वाले अंकुर से हुई थी. दोस्ती में दोस्ती हुई जो समय के साथ प्यार में बदल गई. काजल और अंकुर ने अपने परिवार वालों को मनाया और शादी कर ली. शादी से पहले ही काजल साल 2023 में दिल्ली पुलिस की स्वॉट कमांडो टीम में सिलेक्ट हुई थी. अंकुर भी दिल्ली रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर लग गया था. हालांकि, शादी के 15 दिन बाद ही अंकुर के घर वाले गाड़ी और दहेज की मांग करते हुए काजल को परेशान करने लगे थे.

काजल के सिर के कई हिस्सों में गहरी चोटें थीं

पुलिस के मुताबिक, 22 जनवरी को रात करीब 10 बजे मोहन गार्डन स्थित फ्लैट में पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। इसी दौरान आरोपी अंकुर ने काजल पर जानलेवा हमला कर दिया. हमले में काजल के सिर पर गंभीर चोटें आईं और वह मौके पर ही बेहोश हो गई. आरोपी अंकुर ही गंभीर रूप से घायल काजल को मोहन गार्डन स्थित तारक अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों की रिपोर्ट में सिर के कई हिस्सों में गहरी चोटें, कट के निशान और कान से खून बहने की पुष्टि हुई.

सीएम ममता बनर्जी सोमवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिलेंगी

बंगाल। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की प्रमुख ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल अगले सप्ताह सोमवार शाम को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेगा। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुमार ने बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल को दो फरवरी को शाम चार बजे मिलने का समय दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा था कि वह राज्य में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ जल्द ही दिल्ली जाएंगी। बनर्जी ने एसआईआर के नाम पर लोगों का अकथनीय उत्पीड़न करने के लिए निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला किया।

यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट, दुरुपयोग का खतरा... सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने) विनियम, 2026 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट में इन विनियमों को सामान्य वर्गों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण होने के आधार पर चुनौती दी गई है। ऐसे में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी। अब नए आदेश तक 2012 के नियम ही लागू रहेंगे।

केंद्र को नोटिस जारी, 19 मार्च को अगली सुनवाई

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि नए नियम अस्पष्ट हैं। कोर्ट ने कहा कि नए यूजीसी नियमों का दुरुपयोग हो सकता है।

इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।

केंद्र और यूजीसी से जवाब मांगा

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इन रिट याचिकाओं की सुनवाई की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि हमें जातिविहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए या हम पीछे जा रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे। जिन्हें सुरक्षा चाहिए, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने केंद्र और यूजीसी से जवाब मांगा है।

साथ ही कहा है कि एक विशेष कमेटी भी बनाई जा सकती है। इसी के साथ नए नियमों की भाषा को स्पष्ट करने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत पर भी जोर दिया।

केंद्र को नया ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश; अगले आदेश तक 2012 वाले नियम लागू, देशभर में नियमों का विरोध

परिवार समेत समर्थकों ने नम आंखों से दी विदाई; अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसैलाब

***अजित पवार का अंतिम संस्कार, पत्नी ने गंगाजल चढ़ाया, बेटों ने मुखाग्नि दी**
*** गन सैल्यूट दिया गया; शाह और शरद पवार मौजूद रहे**

बारामती। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को गुरुवार को उनके गृहनगर बारामती में अंतिम विदाई दी गई। एक दुखद विमान हादसे में उनके निधन के बाद पूरे राज्य में शोक की लहर है। अजित पवार का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में भारी संख्या में समर्थक अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने पहुंचे।

अजित दादा अमर रहें के नारे से गूंजा बारामती

अंतिम संस्कार की रस्में दोपहर में शुरू हुईं। अजित पवार के बेटों, पार्थ और जय ने अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान उनकी पत्नी और राज्यसभा सदस्य सुनेत्रा पवार अपने आंसू नहीं रोक पा रही थीं। जब उनके पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय ध्वज में लिपटा हुआ उनके गांव काटेवाड़ी से विद्या प्रतिष्ठान मैदान लाया गया। मैदान में मौजूद हजारों लोगों ने अजित दादा अमर रहें के नारे लगाए, जिससे पूरा माहौल गमगीन हो गया।

अंतिम संस्कार में शामिल हुए कई केंद्रीय मंत्री

इस दुखद घड़ी में देश और राज्य के कई बड़े नेता बारामती पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, मुरलीधर मोहोल और भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। अजित पवार के चाचा और एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार भी वहां मौजूद थे। वे पूरे समय चुपचाप बैठे रहे और अपने भतीजे को अंतिम विदाई दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी पुणे से बारामती पहुंचे और पुष्पचक्र अर्पित किए। अजित पवार की चचेरी बहन और सांसद सुप्रिया सुले पूरे समय सुनेत्रा पवार के साथ खड़ी रहीं और उन्हें सांत्वना देती रहीं। अंतिम संस्कार में प्रफुल्ल पटेल, रामदास अठावले, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, पूर्व मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे और अशोक चव्हाण जैसे दिग्गज नेता भी शामिल हुए। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी काटेवाड़ी जाकर अजित पवार को श्रद्धांजलि दी। अभिनेता रितेश देशमुख भी इस मौके पर मौजूद थे।

विकसित भारत 2047 के लिए अगले 25 साल का अहम पड़ाव शुरू - पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बजट सत्र की शुरुआत के अवसर पर संसद पहुंचे। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने आगामी बजट के महत्व और देश की आर्थिक दिशा पर विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह बजट सत्र केवल एक वार्षिक वित्तीय लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है पीएम मोदी ने कहा कि कल राष्ट्रपति का भाषण 140 करोड़ भारतीयों के भरोसे को दिखाता है और उनकी क्षमताओं और आकांक्षाओं, खासकर युवाओं की आकांक्षाओं को बताता है। उन्होंने कहा कि इस भाषण ने 2026 सत्र की शुरुआत में सभी सांसदों को मार्गदर्शन दिया है, और विश्वास जताया कि सांसद राष्ट्रपति द्वारा बताई गई उम्मीदों को गंभीरता से लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं, 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। यह अगले चौथाई हिस्से की शुरुआत है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए, इन 25 सालों का महत्वपूर्ण चरण शुरू हो गया है। सदी के इस दूसरे चौथाई हिस्से का पहला बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की पहली वित्त मंत्री हैं, देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं जो लगातार 9वीं बार संसद में बजट पेश कर रही हैं। यह देश के संसदीय इतिहास में एक गौरवशाली क्षण के रूप में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री के संबोधन ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का विजन दीर्घकालिक है। अब सभी की निगाहें वित्त मंत्री के पिटारे पर टिकी हैं कि वह विकसित भारत के इस दूसरे चरण की नींव कैसे रखती हैं। प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि वह देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं, जो लगातार नौवीं बार संसद में बजट पेश करने जा रही हैं। उन्होंने इसे संसदीय इतिहास का गौरवपूर्ण क्षण बताया। इसके अलावा, पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संबोधन 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास, क्षमता और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है, खासकर युवाओं की उम्मीदों का। पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि राष्ट्रपति द्वारा संसद सदस्यों को दिए गए संदेश को सभी सांसद गंभीरता से लेंगे।

संत रविदास जयंती समारोह की तैयारियां पूरी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे कई घोषणाएं

चंडीगढ़।

हरियाणा सरकार और दलित संगठनों की ओर से 31 जनवरी को कुरुक्षेत्र के उमरी में मनाई जाने वाली संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय ऊर्जा, आवासन व शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल संत रविदास जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए दलित कल्याण की कई घोषणाएं कर सकते हैं। पूरे प्रदेश से दलित समाज के लोग संत रविदास जयंती समारोह में भागीदारी करने कुरुक्षेत्र के उमरी में पहुंचेंगे। हरियाणा सरकार की ओर से संत-महापुरुषों की जयंतियां नियमित रूप से मनाई जा रही हैं। संत रविदास के जयंती समारोह में हरियाणा सरकार के साथ हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान जन चेतना ट्रस्ट मुख्य

आयोजक की भूमिका में है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के मुख्य मीडिया सलाहकार और जन चेतना ट्रस्ट के संयोजक सुदेश कटारिया ने संत रविदास जयंती की तैयारियों के लिए पूरे राज्य का दौरा किया। कार्यक्रम स्थल का अवलोकन करने के बाद सुदेश कटारिया ने कहा कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जयंती समारोह में दलितों के उत्थान की नई योजनाओं की घोषणा करेंगे। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार की ओर से मुख्यमंत्री को दलित समाज की ओर से एक मांगपत्र सौंपा जा चुका है। सुदेश कटारिया ने बताया कि हरियाणा सरकार महापुरुषों और संतों को सम्मान प्रदान करने के लिए लगातार राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर लाल ने यह परंपरा आरंभ की थी, जिसे मौजूदा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरे सम्मान के साथ निभा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के उमरी में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दलित मंत्रियों, भाजपा नेताओं और दलित संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। भाजपा एससी मोर्चा की ओर से भी कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं। जनचेतना ट्रस्ट के संयोजक सुदेश कटारिया के अनुसार राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 14 जिलों पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, जींद, हांसी, झज्जर तथा फतेहाबाद से ब्लाक स्तर तक और शेष नौ जिलों से जिला स्तर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार, भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जरावता, पूर्व मंत्री डा. बनवारी लाल, नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी, भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया समेत कई दलित नेता जुटे रहे। कटारिया ने बताया कि इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।

अविमुक्तेश्वरानंद का विवाद हाई कोर्ट पहुंचा, अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिए जाने की मांग

प्रयागराज। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और माघ मेला प्रशासन का विवाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष पत्र याचिका (लेटर पिटीशन) दाखिल कर 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या पर हुई घटना की सीबीआई से जांच करवाने और प्रयागराज कमिश्नर, डीएम, पुलिस कमिश्नर तथा मेला अधिकारी को निलंबित करने का आदेश देने की मांग की है। याचिका में नाबालिग बटुकों को हिरासत में रखकर उनसे मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की गई है। याची के अनुसार, माघ मेला सनातन धर्म का पवित्र उत्सव है। इसमें मौनी अमावस्या का स्नान सबसे महत्वपूर्ण है। इस बार मौनी अमावस्या पर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जब संगम स्नान के लिए शिष्यों के साथ पालकी से जा रहे तभी प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने उनको जबरदस्त पालकी से उतार दिया और और पैदल स्नान जा कर स्नान करने के लिए कहा। साथ चल रहे 11 से 14 वर्ष के बटुकों को हिरासत में लेकर मारा-पीटा तथा उनकी शिखा (चोटी) पकड़ कर घसीटा गया। नाबालिग बटुकों से ऐसी यादती जुवेनाइल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन एक्ट के प्रविधानों का उल्लंघन होने के साथ दंडनीय अपराध है। बटुकों की शिखा खींचना सनातन धर्म को अपमानित करना है। मेला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले का हवाला देकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पद को लेकर सवाल उठाए हैं। शंकराचार्य की नियुक्ति की तय धार्मिक प्रक्रिया है, जो अखाड़ों और काशी विद्वत परिषद के माध्यम से संपन्न होती है। प्रशासन को उस पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है।

इंडिया गठबंधन में पहली बड़ी दरार? चंडीगढ़ में कांग्रेस-आप की जंग ने बीजेपी को जिताया

चंडीगढ़।

गुरुवार सुबह भाजपा के सौरभ जोशी चंडीगढ़ के नए महापौर चुने गए। कागज पर सहयोगी माने जाने वाले आम आदमी और कांग्रेस के बीच संयुक्त रणनीति पर सहमति नहीं बन पाने के कारण यह चुनाव विफल रहा। जोशी को 18 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के योगेश ढिंगरा को 11 और कांग्रेस के गुरप्रीत सिंह गाबी को सात वोट मिले। भाजपा ने दो उप महापौर पद भी जीत लिए। जसमनप्रीत सिंह वरिष्ठ उप महापौर और सुमन शर्मा उप महापौर चुने गए। सिंह और शर्मा दोनों को 18-18 वोट मिले। कांग्रेस ने उप महापौर पदों के लिए चुनाव नहीं लड़ा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव जीतने के बाद, भाजपा के सौरभ जोशी ने कहा कि वरिष्ठ नेतृत्व ने जिस तरह से मुझ पर भरोसा जताया और मुझे यह

अवसर दिया, उसे देखते हुए मैं बूथ स्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा कि मैं पहली बार 1989 में बूथ पर बैठा था और आज वरिष्ठ नेतृत्व ने मुझे इस पद तक पहुंचाया है। मेयर चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को 35 पार्षदों वाली विधानसभा में 19 वोटों की आवश्यकता होती है। भाजपा के पास 18 पार्षद हैं, जिनमें से सभी ने अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया। आम आदमी पार्टी के पास 11 और कांग्रेस के पास सात पार्षद हैं, जिनमें उसके चंडीगढ़ सांसद मनीष तिवारी का वोट भी शामिल है। इसका मतलब यह था कि कांग्रेस-आप गठबंधन - जिससे दोनों पक्षों को 18-18 वोट मिलते ही भाजपा को इस चुनाव में पूर्ण जीत से रोकने का एकमात्र तरीका था। अगर ऐसा होता, तो नियमों के अनुसार, सिक्का उछालकर चुनाव का फैसला हो सकता था।

लेकिन पिछले हफ्ते आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी ने देश को लूटा है। पार्टी के अनुराग ढांडा ने कहा कि कांग्रेस के साथ कभी कोई गठबंधन नहीं हो सकता, जबकि कुछ ही दिन पहले कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि वे आप के साथ बातचीत कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने पाखंड से भरा हुआ देश के नाम संदेश दिया- कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद के हर सत्र की तरह इस बार भी पाखंड से भरा देश के नाम संदेश दिया है। बजट सत्र की शुरुआत में संसद भवन परिसर में अपने पहले पारंपरिक संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश लंबे समय से लंबित समस्याओं से बाहर निकल रहा है और दीर्घकालिक समाधान की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब समय व्यवधान खड़े करने का नहीं, बल्कि समाधान खोजने का है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद महासचिव जयराम रमेश ने 'एक्स पर पोस्ट किया, वह (प्रधानमंत्री) राष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्ष को विश्वास में लेने के लिए न तो सर्वदलीय बैठकों को बुलाएंगे और न ही उनकी अध्यक्षता करेंगे। वह आखिरी समय में विधेयक पेश कराएंगे और आवश्यक विधायी जांच-पड़ताल के बिना उन्हें संसद में बुलडोजर से पास करवा लेंगे। उन्होंने कहा, ''वह संसद में बैठकर विपक्षी नेताओं की चिंताओं का जवाब देने के बजाय दोनों सदनों में चुनावी रैली जैसे भाषण देंगे। हर सत्र की शुरुआत से पहले वह संसद को पृष्ठभूमि बनाकर अपना हमेशा की तरह पाखंड से भरा हुआ 'देश के नाम संदेश' देंगे। उन्होंने कटाक्ष किया, ''आज का प्रदर्शन उसी सिलसिले की एक कड़ी है।

अखिलेश का बीजेपी सरकार पर तंज- प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में नहीं बनने दी जा रही मेट्रो

ग्रेटर नोएडा।

समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट, नोएडा इंजीनियर मौत मामले और यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, प्रधानमंत्री अपने भाषण में भारत को सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क मिलने की बात कह रहे हैं,

लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम, प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में मेट्रो निर्माण नहीं होने दे रहे हैं।

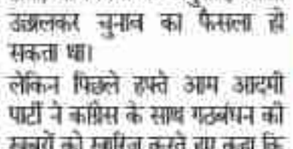

इंजीनियर मौत मामले पर यह बोले

नोएडा में हुई इंजीनियर की मौत के मामले पर कहा, जब उन्हें मदद की जरूरत थी, तब उन तक मदद क्यों नहीं पहुंची?

हमें पता चला है कि पीड़ित का परिवार गुजरात से है। प्रधानमंत्री के गुजरात से होने के बावजूद सरकार उस व्यक्ति को नहीं बचा सकी।

यूजीसी नियम पर रोक लगाए जाने पर कही यह बात

साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन पर रोक लगाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, यूजीसी के मामले में जो बातें निकलकर आ रही हैं, हमारा मानना है कि दोषी ना बचे और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो। इससे पहले भी 2012 में रेगुलेशन आए थे... हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हमारे तमाम कानूनों के बावजूद समय-समय पर भेदभाव होता है।